consultation with trade, industry and other concerned institutions including FIEO. All suggestions for export promotion including those by FIEO in the Export Strategy Paper are welcome. Exports have been made into a national priority and the Government is very keen to provide an export friendly environment to the exporting community backed by proper infrastructure.

गुजरात में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना

1312. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्य में कुछ अतिरिक्त डिपुओं की स्थापना करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो उसका स्थान-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) गुजरात में दो इनलैंड कन्टेनर डिपो (आई सी डी) एक साबरमती में तथा एक सूरत में कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त अहमदाबाद में अदालाज नामक स्थान पर एक कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी एफ एस) भी कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ) आई सी डी/सी एफ एस की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों को एक ही स्थान पर क्लीयरेन्स प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय में एक अन्तःमंत्रालयी समिति कार्य कर रही है। ऊपर बताए गए कार्यरत आई सी डी/सी एफ एस के अतिरिक्त अन्तः मंत्रालयी समिति ने गुजरात में कांडला, सूरत, बड़ौदा, नासिक और पोरबन्दर में 5 अन्य कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

सुपर बाजार में अनियमितताओं की समीक्षा

1313. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार के कार्यकरण और उन अधिकारियों के कार्य की समीक्षा की है जिन्हें सुपर बाजार के बिक्री सहायकों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अधिकतम अनियमितताएं सुपर बाजार के फर्नीचर, किराना और वस्त्र विभागों में पाई गई थीं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ङ) जी, हां। सुपर बाजार के समग्र कार्यकरण की मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्योंकि सुपर बाजार एक स्वायत्त सहकारी सोसाइटी है, अतः इसका अपना एक समीक्षा तथा नियंत्रण तंत्र है। वहां एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को भी महाप्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है। सूचित की गई अनियमितताओं पर सुपर बाजार के प्रबंधन द्वारा उनके लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विचार किया जाता है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि क्योंकि उनके व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा किराने की वस्तुएं हैं, अतः किराना विभाग के बारे में अधिक शिकायतें मिलती हैं। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि कपड़े तथा घरेलू सामान के विभागों द्वारा की गई आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में हाल में प्राप्त एक शिकायत की उनके सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। घरेलू सामान विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को की गई आपूर्ति से संबंधित मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।